IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में नोटबंदी के आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन

डॉ. मनोज कुमार रंगारी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)

वीरांगना रानी अवन्ती बाई लोधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रामाटोला

जिला – राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

सारांश (Abstract)

भारत में नोटबंदी के संबंध में पुणे के इंजीनियर एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था अर्थ क्रांति संस्था के सुझाव पर नोटबंदी का फैसला लिया गया। संस्थान ने प्रस्ताव को पैटर्न कराया है। मैकेनिकल इंजीनियर अनिल वोलिक–प्रमुख थे। संस्था का दावा है कि यह प्रस्ताव काला धन, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, आतंकियों को फंडिंग रोकने में पूरी तरीके से कारगर साबित होगा। प्रॉपर्टी, जमीन, ज्वेलरी एवं घर खरीदने में ब्लैक मनी का उपयोग में लगाम लगेगी। साथ ही जाली नोटों के लेनदेन पर रोक लगेगी। नौकरी पेशा लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादातर परिवारों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा। तदानुसार वर्ष नवंबर 2016 में भारत के मौद्रिक इतिहास में अभूतपूर्व घटना घटित हुई थी जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी घोषणा के अनुरूप बड़े नोटों का चलन बंद कर दिया था। तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा था कि लगभग 86 प्रतिशत वैधानिक मुद्रा चलन से बाहर हो गई थी तथा नगदी का संकट पैदा हुआ। देश की जनता को पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा में बदलने की छूट सीमित आधार पर दी गई। तथा नई मुद्रा की आपूर्ति में समय विलंबता के कारण नगदी का संकट गहराया। नोटबंदी के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 तथा 2000 रूपये के लगभग 14 लाख करोड रुपये की नई मुद्रा जारी की है, लेकिन अधिकृत रूप से आरबीआई यह घोषित करने में समर्थ नहीं रहा है कि बैंकों ने देश की जनता से कितनी पुरानी मुद्रा जमा की।

कुंजी (Keywords) - नोटबंदी, कालाधन, आर्थिक स्थिति, मुद्रा।

प्रस्तावना (Introducation) –

जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8:15 बजे नोटबंदी की घोषणा की तो सारे भारत में भूकंप से आ गया। कुछ लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री भारत और पाकिस्तान के कड़वे होते रिश्ते के बारे में बोलेंगे या शायद दोनों दोस्तों के बीच में युद्ध का ऐलान ही ना कर दे। लेकिन यह घोषणा तो कुछ लोगों के लिए युद्ध के ऐलान से भी घातक सिद्ध हुई उनकी रातों की नींद उड़ गई। कुछ लोग होशोहवास खोते हुए ज्वेलर्स के पास दौड़े व उल्टे–सीधे दामों पर सोना खरीदने लगे। अगले दिन से ही बैंक व एटीएम लोगों के स्थाई पते बन गए। लाइने दिनों दिन भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या

को दर्शाने लगी। सरकार भी कभी लोगों को राहत देने के लिए तथा कभी काला धन जमा करने वालों के लिए नए–नए कानून बनाती देखी। कभी बैंक व एटीएम से पैसे निकलवाने की सीमा घटाना व बढ़ाना व कभी पुराने रूपयों को जमा करवाने के बारे में नियम में शक्ति करना या ढील देना।

विपक्षी दल पूरी एकजुट से सरकार के निर्णय को असफल व देश को पीछे ले जाने वाला सिद्ध करने में लग गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। लगभग पूरा विपक्ष सरकार के इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। मोर्चे, प्रदर्शन रोज प्रकट किए गए। अनेकता में एकता का भाव सार्थक हुआ। दूसरी तरफ सरकार अपने इस निर्णय को सही साबित करने में लगी रही। कभी प्रधानमंत्री व उनकी टीम लोगों को इस नोटबंदी के फायदे गिनने में लग रहे वह कभी 50 दिन का समय मांगते नजर आए। लोगों के अंदर भी बहुत भाईचारा देखने को मिला। अमीर दोस्तों को उनके गरीब नकारा दोस्त याद आए। अमीर रिश्तेदारों को अपने गरीब रिश्तेदारों के महत्व का एहसास होने लगा। अमीर बेटे की गरीब मां का बैंक अकाउंट जो कि पिता की मौत के बाद मर चुका था, अचानक जिंदा हो गया। ऐसा लगा मानो पूरी मानवता जिंदा हो गई।

मीडिया वालों का भी बहुत शानदार रोल रहा। कुछ नोटबंदी पर सरकार के फैसले के पक्ष में खड़े दिखाई दिए व कुछ विपक्ष में कुछ न्यूज चैनल को लोग लाइनों में मजे लेते दिखाई दिए तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को मरते। कुछ चैनल के अनुसार लगभग 100 लोगों ने लाइनों में खड़े होकर अपनी जान गवाई।

नोटबंदी की वजह से पुराने जमाने में सफल बार्टर पद्धति फिर से कारगर सिद्ध हुई। लोगों ने बिना पैसे के भी दिन गुजारने सीख लिए । सच कहूं हमें तो कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। बस थोड़ा समायोजन करना पड़ा देश के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ जरूरी भी है।

नए–नए तरीकों का अविष्कार –

यहाँ कुछ लोगों की बुद्धिमता देखने को मिली। उन्होंने अपने काले धन छिपाने के लिए नए–नए तरीके अपनाए। जैसे गरीब दोस्तों और रिश्तेदारों की बैंक अकाउंट में पैसे डालना मजदूरों को तीन सौ–चार सौ रूपयों में हायर करना। 20 से 30 प्रतिशत के लालच पर पुराने नोटों के बदले नए नोट प्राप्त करना। कुछ बैंक व डाक कर्मचारियों की अवैध सेवाएँ लेना इत्यादि–इत्यादि। सरकार का दावा है कि लगभग चार सौ से साढ़े चार सौ करोड़ रुपए का काला धन बैंक में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब सरकार व इनकम टैक्स वालों की ऐसे बैंक अकाउंट पर पूरी नजर है।

प्रधानमंत्री ने काले धन के खिलाफ नोटबंदी की घोषणा कर समानांतर आर्थिक व्यवस्था की ध्वस्त करने के लिए सबसे बड़ा दाव खेल नोटबंदी जैसा कदम है। जिसमें समूचा भारत व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बडा, क्या बुजुर्ग, महिलाएँ हर व्यक्ति को नोटबंदी के फैसले ने गहराई तक प्रभावित किया है।

यह हुआ ऐलान

- 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद।
- 9 से 10 नवंबर 2016 को देश के सभी बैंक बंद। 24 नवंबर 2016 तक अस्पताल मेडिकल स्टोर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन पर नोट चलेगी साथ ही बिजली पानी राजस्व जमा में भी स्वीकार किए गए।
- 30 दिसंबर 2016 तक 500 और 1000 के नोट बैंक और पोस्ट ऑफिस में बदले जा सकते हैं।
- एक दिन में सिर्फ 10 हजार तक नोट बदले जा सकते हैं। लगातार जमा और बदलने के नियमों में फेर बदल हर दूसरे दिन जारी हुआ। 31 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक में पुराने बड़े नोट बदले जा सकते हैं।
- 10 नवंबर 2016 से बाजार में 500 एवं 2000 के नए नोट आएंगे और आरबीआई के अनुसार आजादी के बाद 9.11.2016 शायद पहला दिन जब किसी रिश्वतखोर ने रिश्वत न ली हो..... चोर ने चोरी ना कि हो..... किसी बहू ने दहेज लोभियो के मांग पर आत्महत्या के लिए मजबूर नही होना पड़ा है.....अपहरणकर्ताओं ने फिरौती और हत्यारे के द्वारा सुपारी ना मांगी गई हो... पत्थरबाजो ने पत्थर ना फेक हो और आतंकवादियों ने गोली चलाने से मना कर दिया हो।

4जी लेवल का सिम लेने महीने भर में 1 किलो लगने वाला नमक खत्म होने की अफवाह ने बाद देर रात्रि सुबह और सुबह 3 बजे से लाइन में खड़े रहकर ऐसा व्यवहार किया मानो एटीएम या बैंक के सामने नए नोट लेने या पुराने अमान्य नोट जमा करने के लिए नहीं वरन सीमा पर खड़े हो और सामने से नोट नहीं दुश्मन की गोलियां दागी जा रही है। अवस्था में नित्य नए नियमों में बदलाव लाया गया आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर 74 से ज्यादा (53+21) किया गया। 9 से 13 तक नोटबंदी के चलते बैंक एटीएम पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए । 14 नवंबर से 24 नवंबर तक सेवाओं के लिए जाने की सीमा तय कर दी गई सप्ताह में रुपया निकासी की लिमिट (सीमा) तय रख दी गयी।

कानूनी रूप में किसी मुद्रा इकाई की स्थिति मूल्य को अमान्य कर देना ही विमुद्रीकरण है। मोटे तौर पर या राष्ट्रीय मुद्रा में एक प्रकार का परिवर्तन है जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और लोग नोटों को बैंकों से दूर जमाखोरी करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है। इससे मुद्रा के पुरानी इकाई को सेवानिवृत कर एक नई मुद्रा इकाई के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है जो पुनः बैंकिंग प्रक्रिया में शामिल होकर सरकार को टैक्स (कर) के रूप में सहायक होती है। इस तरह या देश की अर्थव्यवस्था में एक प्राणवायु फूटने का काम करती है।

अब पुराने 500 और 1000 के चलन वाले नोट अब इतिहास हो गए हैं। पूरा देश पुराने नोटों का महात्मा गांधी न्यू सीरीज आफ नोटिस 2016 से बदलने के लिए कतार में लगा है। 1000 का इतिहास 1954 में पहली बार जारी हुआ था जिसे जनवरी 1978 में बंद कर दिया गया। 2000 में दूसरी बार 1000 रूपये का नोट जारी हुआ था 500 रूप्ये के नोट का इतिहास पहली बार अक्टूबर 1987 में जारी हुआ। 2005 में सुरक्षा की दृष्टि से मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले सुरक्षा धागे इलेक्ट्रो टाइप वाटर मार्क नोट जारी

होने का साल आदि के साथ सुरक्षा प्रबंधो व आकार के छापा गया है। बाजार की कुल नगदी में 1000–500 के नोट की हिस्सेदारी 84 फीसदी 1000 के नोट की हिस्सेदारी 39 फीसदी और 500 के नोट की हिस्सेदारी 45 फीस दी है। सन 1900 में 100 नोट आया सन 1905 में 50 रूपये का सन 1960 में 5 रूपये और सन 1909 में 1000 रूपये का नोट जारी हुआ जो कि पूरे भारत में 8 नवंबर की रात 500 और 2000 के नोट का चलन सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया।

उद्देश्य (Object) –

- नशे के कारोबार तथा तस्करी अवैध लेनदेन को ध्वस्त करना।
- आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों के लिए अवैध लेनदेन को ध्वस्त करना।
- बैंकिंग सुविधा से वंचित या काम बैंकिंग सुविधाओं वाले भारतीयों को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाना।
- किसान का नगदी की कमी के कारण रवि फसल की बुवाई में हुई कठिनाई से बाहर निकलना।

नोटबंदी के बाद नगदी की कमी वजह से खपत के मोर्चे पर जो अस्थाई झटका लगा है उसके मध्य नजर वृद्धि दर के अनुमान को कम करना।

नोटबंदी के फायदे –

- काले धन की समाप्ति।
- गरीबों को लाभ चेक से वेतन का भुगतान आतंकवाद समाप्त होगा।
- नकली नोट का चलन बंद होगा।
- महंगाई कम होगी।
- प्लास्टिक मनी का चलन होगा।
- हवाला कारोबार बंद होगा।
- रिश्वतखोरी, घूसखोरी में कमी या फिर पूरी तरह से बंद होगा।
- जमीनों के भाव कीमतों में कमी होगी।
- शिक्षा सस्ती होगी। Donation कम होगा सोने के दामों में कमी आएगी।
- समाज में स्थायित्व आएगा।
- लोगों में समानता व एकता का भाव आएगा।
- काला धन का उपयोग न कर पाएंगे ।
- देश का तरक्की विकास होगा।
- ब्याज दरों में कमी लोगों के बीच बैंकों द्वारा कम ब्याज पर लोन उपलब्ध रहेगी।
- राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।

नुकसान –

- छोटे व्यापारी जिनका व्यवसाय नगद कैश पर चलता है। सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
- दूधवाला
- किराना व्यापारी
- लेखन सामग्री
- मिठाई वाला
- अखबार वाले दैनिक
- मजदूरी करने वाले श्रमिक
- बूट पॉलिश करने वाले श्रमिक
- सब्जी वाले इत्यादि नोटबंदी से सबसे अधिक प्रभावित हुए और आगे भी होते रहेंगे।

1921 से 1927 के बीच जब मुसोलिनियों ने इटली की करेंसी लीरा को बंद करके अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बाकी 2009 इटली की करेंसी पर विश्वास करना बंद कर दिया। कुछ ही वर्षों में इटली आर्थिक रूप से कंगाल हो गया जर्मनी में हिटलर ने करंसी बंद कर दी तो एक वेलियन मार्क से भी दिन भर की रोटी नहीं खरीद पा रहे थे। हिटलर ने यह स्टालिन को नीचा दिखाने के लिए किया, लेकिन इसका गंभीर परिणाम निकला यह तब तक जारी रहा जब तक 1933 में नेशनल सोशलिस्ट सत्ता में नहीं आ गये।

1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने काले धन पर काबू पाने के लिए 50 और 100 रूबल को बंद कर जो कुल करंसी का एक तिहाई हिस्सा हुआ करते हैं। 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया किंतु यह नहीं सोच की साइड इफेक्ट कितने भयानक हो सकते हैं। नोटबंदी ने न आम जनता का जीना मुहाल कर दिया बल्कि व्यापार एवं दूसरे धंधे पर भी बुरा प्रभाव डाला है। नोटबंदी के व्यापक प्रभाव हुए हैं। जिनका समय–समय पर आकलन करना अति आवश्यक है। नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य काले धन की अर्थव्यवस्था पर करारी चोट मारना था तथा देश में कर आधार व जीडीपी कर अनुपात में वृद्धि करना था। देश की ऐसी जनता को कर के दायरे में लाना था जो की आय तो अर्जित करती है लेकिन छुपाती भी है तथा कर के दायरे में बाहर रहती है।

5 अगस्त 2017 तक भारतीय कर विभाग का मानना है कि गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत कर विवरणी का अधिक जमा हुई है। जो की कर आधार को विस्तृत करने का प्रबल आधार है तथा आयकर से राजस्व में भी तेजी से वृद्धि करेगी गत वर्ष में कुल 2.27 करोड़ टेक्स रिटर्न जमा हुई थी। जो की बढ़कर 2.79 करोड़ हो गई वृद्धि दर 10 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई नोटबंदी ने ऐसे करदाताओं को टैक्स रिटर्न भरने के लिए बाध्य कर दिया जिन्होंने अपने वह अन्य खाते में जितने नोट जमा करवा उतनी आया तो दर्शाती नहीं या कम दर्शाइ गई। भारतीय आयकर विभाग में लगभग 18

लाख ऐसे मामले सर्च किए हैं जिन्होंने 2 लाख से अधिक की नगदी जमा करवाई। लगभग आधे कर धारकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। तथा यह मानना है कि लगभग एक व्यक्ति संदेह के घेरे में हैं जिन्होंने लगभग 1.72 लाख करोड रुपए से अधिक की नगदी जमा करवाई है। नोटबंदी का सकारात्मक प्रभाव यह भी पड़ा है कि निवेश परंपरागत जगह के स्थान पर वित्तीय उत्पादों की तरफ प्रवृत्त हुआ है। परंपरागत रूप से निवेश रियल एस्टेट जेम्स एवं ज्वेलरी सोने चांदी आदि धातुओं में किया जाता है। लेकिन म्युचुअल फंड में निवेश में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्ष 2015–16 में म्युचुअल फंड में निवेश 1.34 लाख करोड़ हुआ है। जो कि वर्ष 2016–17 में बढ़कर 3.43 लाख करोड़ हो गया है। मात्र 3 महीना में अप्रैल से जून 2017 में लगभग 93 हजार करोड रुपए की वृद्धि हुई है रियल एस्टेट, जमीन जायजा सोना–चांदी, जेम्स एवं ज्वेलरी में काले धन का उपयोग अधिक किया जाता है। नगदी के माध्यम से लेनदेन अधिक किए जाते हैं जो की कर के दायरे में नहीं आते थे लेकिन वित्तीय उत्पादों जैसे म्युचुअल फंड, जीवन बीमा पॉलिसी, अंश बाजार, बैंक एफडी ऋण पत्रों में निवेश से समस्त लेन–देन बैंक खातों के माध्यम से होगा तथा काले धन पर रोक लगेगी। आय स्रोत बताना होगा तो कर राजस्व में वृद्धि होगी।

ऑपरेशन क्लीन मनी पर कार्य करना होगा तथा यह संदेश जनता को देना होगा कि यदि उनकी आया है तो कर तो देना ही होगा चाहे वह कितना भी बड़ा हुआ क्यों न हो। प्रभावशाली व्यक्ति उद्योगपति व्यापारी क्यों ना हो। लगभग 322 सेल कंपनियों के अंशु के लेनदेन पर सेबी ने रोक लगा दी है। यह वे कंपनियां है जो कि कृत्रिम कंपनियां हैं जो की कागज पर कार्य कर रही है, तथा भौतिक अस्तित्व नहीं है जो यह कार्य करते हैं। उन पर यह करारी चोट है। मोदी सरकार ने नोटबंदी के अलावा बेनामी लेने–देन व दिवालिया कानून बनाया है जिसका क्रियान्वयन यदि प्रभावित तरीके से होगा तो काले धन के सृजन एवं परिणामों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

लेकिन आरबीआई द्वारा भारत सरकार को देय लाभांश में व्यापक कमी आई है। वर्ष 2016 में या लाभांश लगभग 65000 करोड़ रूपया था जो कि वर्ष 2017 में घटकर 30000 करोड़ हो गया है। इसका कारण यह रहा है कि नोटबंदी के कारण बैंकों के पास अतिरिक्त जमा में तेजी से वृद्धि हुई है। जिस पर जमा धारको को ब्याज देना पड़ रहा है लेकिन बैंकों ने यह पैसा भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करवा दिया। जिस पर आरबीआई को ब्याज देना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त नई मुद्रा के प्रशासन व निर्गमन की लागत लगभग 13000 करोड़ आई है जो की चार गुना अधिक है। नोटबंदी का निर्णय तभी सफल माना जाएगा जबकि इसके उद्देश्य प्राप्त किए जाएं तथा बड़ी मुद्दा के लेनदेन पर नजर रखी जाए। देश के आमजन पर कर का बोझ घटे तो नोटबंदी सफल मानी जाएगी लेकिन प्रभावों पर कड़ी नजर रखना आवश्यक है।

आज देश के चंद उद्योगपतियों को छोड़कर शेष बड़े–बड़े औद्योगिक घराने भी मोदी के फैसले की निंदा कर रहे हैं क्योंकि मिलो में काम करने वाली लेबर यानी सबसे गरीब तपके फैसले की मार से सबसे अधिक पड़ी है, जहाँ उद्योगों निर्यातकों को अपने सप्लाई आर्डर कैंसिल कर भारी घाटा उठाने के

लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वही दिल्ली से यूपी या बिहार जाने वाली ट्रेनों की भीड़ यह बात चिखचिखकर कह रही है कि लोग कई सालों तो कई महीनो कड़ी मेहनत कर कमाए गए पैसों के कागज बन जाने के कारण शहर छोड़ खाली हाथ गांव को लौटाने को मजबूर हैं।

आलम यह है कि ठेकेदारों दुकानदारों व छोटे उद्योगपतियों ने अपने कर्मचारियों व मजदूरों का भुगतान करने से मना कर दिया है। नतीजतन उन्हें भूखे रहने की नौबत आ गई है जिन लोगों के खाते में पैसे भी हैं। वह सहजता से उसे निकाल पा रहे हैं मोदी जी के निर्णय से अपने ही कमाए पैसों से गरीब तपके का जैसा भरोसा सा उठ गया है। नोटबंदी का या दूर हमें कहां ले जाएगा यह कोई नहीं जानता। लगता है मोदी जी ने इन्हें तमाम पहेलियां को पूरी तरह अनदेखा किया या फिर एनपीए का बोझ झेल रहे बैंकों व दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके। व दिवालिया हो चुके अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में इतने दबाव में आ गए कि उन्होंने अपने एक निर्णय के लिए पूरे देश को ही दाव पर लगा दिया। 100 से अधिक लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं क्या यह उदाहरण कम है। मोदी जी को यह बताने के लिए कि ऐसे फैसलों से सिर्फ आर्थिक असंतुलन बढ़ता है। हासिल कुछ नहीं होता। हमारे देश में नोटबंदी के बाद जनार्दन रेड्डी के घर में हुई 500 करोड़ की एक शादी हो या सरकार के मंत्री के पास पकड़ी गई नए नोटों की भारी खेप देश में भारी आर्थिक असंतुलन के एक बड़े खेल की ओर इशारा कर रही है। लगता है कि चांद उद्योगपतियों ने सत्ता के साथ मिलकर देश को तबाह करने का एक भयानक खेल खेला है। 500 और 1000 की चलन में नोटबंदी के चलते आम लोगों की भारी परेशानियों को मध्य नजर सरकार ने पुराने नोटों को जरूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने की सीमा 4 नवंबर से बढ़कर 24 नवंबर की मध्यरात्रि तक कर दी है। बैंकों को कम से कम 50 फीसदी हजार रुपए का कैश लिमिट बढ़ाने की सलाह दी गई। वहीं 14 नवंबर से एटीएम से एक बार धन निकासी की सीमा 2000 से बढ़कर 2500 की गई है। कैश एक्सचेंज की लिमिट को 4000 से बढ़कर 4500 कर दी गई है। बैंक से साप्ताहिक धन निकासी की सीमा मंत्रालय के विश्लेषण के मुताबिक पहले चार दिनों नवंबर 10 से नवंबर 13 शाम 5:00 बजे तक बैंक सिस्टम में 3 लाख करोड रुपए के 500 और 1000 के नोट जमा किए गए हैं।

निष्कर्ष (Conclusion) -

इस प्रकार भारत में नोटबंदी के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नोटबंदी की वजह से जैसे कि कुछ अर्थशास्त्रियों एवं राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय अर्थ संबंधी संगठनों ने दावा भी किया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे कुछ और जानकारी के अनुसार नोटबंदी की वजह से नकली नोट छापने का कारोबार खत्म हो गया है। जिसकी वजह से देश में से बहुत मात्रा में नकली नोट व उनसे संबंध अवैध कारोबार भी खत्म हो गए हैं।

संदर्भ (Refrences) -

1. डॉ. गंगवाल, सुभाष भारत, में नोटबंदी के प्रभाव दैनिक नवज्योतिडॉटइन 21.08.2017.
2. नोटबंदी समीक्षा समाचार पत्र दैनिक भास्कर स्टार समाचार पत्रिका और दैनिक जागरण.
3. जोशी नवीन– (9 नवंबर 2016 पेज 9) jagaran.com नोटबंदी के नफा नुकसान.
4. सिंह जवाहरलाल : नोटबंदी की सफलता पर मोदी.
5. दिसंबर 04.2016 jayvijay.com 14/11/2016.
6. हिंदुस्तानी सुरेंद्र (नवंबर 27.2016) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा भारत बंद.
7. डॉ धर्मेंद्र कुमार नोटबंदी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन (अप्रैल से जून 2019).
8. www.patrika.com/Note-on-mounting-the step.ob.the capotive growth india.